सुधीर मित्तल से पहले, जे.

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड।— याचिकाकर्ता

बनाम

सीमा गांधी और अन्य-2018 के उत्तरदाता एफ. ए. ओ. No.1900

26 मार्च, 2021

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-अधिनियम के धारा.163-A और धारा.166 के तहत उपलब्ध उपचार अलग और विशिष्ट हैं-एक साथ कार्यवाही नहीं की जा सकती है-धारा.163-A के तहत दायर मूल दावे के बाद धारा.166 के तहत दावा करने के लिए कोई रोक नहीं है-S.163-A के तहत उपचार 'कोई दोष दायित्व नहीं' के आधार पर है और Rs.40,000/- से कम कमाने वाले दावेदार के लिए है, जबकि धारा.166 के तहत उपचार 'दोष दायित्व' के आधार पर है।

यह मानते हुए कि, जवाब में, दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की खंड 163-ए और 166 के तहत उपचार स्वतंत्र हैं और दावेदार दोनों का लाभ नहीं ले सकता है, हालांकि, क्योंकि अधिनियम की खंड 163-ए के तहत याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया था, अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका थी

बनाए रखने योग्य।दीपाल गिरीशभाई सोनी (ऊपर) में निर्णय नहीं है

इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित हुए।

(पैरा 4)

ने आगे अभिनिर्धारित किया कि, इस प्रकार, कानून यह है कि अधिनियम की खंड 163-ए और खंड 166 के तहत एक साथ कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें उपचार अलग और स्वतंत्र हैं।खंड 163-ए के तहत प्रदान किया गया उपाय नो-फॉल्ट लायबिलिटी के आधार पर है और इसे एक दावेदार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जोड़ा गया है, जिसकी आय 5 लाख रुपये से कम है। 40, 000/- प्रति माह। उक्त कार्यवाहियां अधिनियम की खंड 140 के तहत होने वाली कार्यवाहियों के विपरीत प्रकृति में अंतिम हैं।

(पैरा 8)

ने आगे कहा कि, तत्काल मामले में, हालांकि न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम की खंड 163-ए के तहत दावेदार की याचिका को अनुमति दी गई थी, अपील में, पुरस्कार को दरकिनार कर दिया गया था और एक निष्कर्ष वापस कर दिया गया था कि उक्त याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि दावेदार की आय रुपये से बहुत अधिक थी। 40, 000/- प्रति माह। इन परिस्थितियों में, दावेदार पर गलती दायित्व के आधार पर अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका दायर करने पर कोई रोक नहीं थी।यह दो अलग-अलग और स्वतंत्र प्रावधानों का लाभ उठाने के बराबर नहीं है।यदि दावेदार ने 704 लिया था

अधिनियम की खंड 163-ए के तहत याचिका पर पारित पुरस्कार का लाभ और फिर अधिनियम की खंड 166 के तहत एक याचिका दायर की थी, अपीलकर्ता का यह तर्क देना सही होगा कि अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका पर रोक थी।

(पैरा 9)

राधिका सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

नीरज खन्ना, अधिवक्ता और

मनप्रीत कांडा, अधिवक्ता

अपीलकर्ता के लिए

अश्विनी अरोड़ा, प्रतिवादी नं. 1 के लिए अधिवक्ता

सुधीर मित्तल, जे।

(1) बीमा कंपनी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 07.12.2017 के फैसले के खिलाफ अपील कर रही है। 2,99,839-दावेदार को दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि 14.10.2011 पर एक मोटर दुर्घटना हुई थी।दावेदार-सीमा गांधी एक एक्टिवा स्कूटर पर सवार थीं, जिसे चंडीगढ़ के सेक्टर 20-डी में हाउस नंबर 3062 के पास होंडा सिटी कार ने टक्कर मार दी।नतीजतन, दावेदार को चोटें आईं। वाहन के चालक के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, हालांकि, डी. डी. आर. दिनांक 16.10.2011 पूर्व। पी-53 दर्ज किया गया था।दावेदार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की खंड 163-ए के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें रुपये 1,09,000/- का मुआवजा दिया गया। दिनांकित 19.11.2013 के माध्यम से किया गया था।इसे 2014 के एफ. ए. ओ. सं. 1815 में चुनौती दी गई थी, जिसे इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि अधिनियम की खंड 163-ए के तहत दावा याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि दावेदार की आय प्रति वर्ष Rs.40,000/- से बहुत अधिक थी। नतीजतन, वर्तमान याचिका अधिनियम की खंड 166 के तहत दायर की गई थी और इसे दिनांक 7.12.2017 के अवार्ड के माध्यम से अनुमति दी गई है।उतावलापन और लापरवाही से गाड़ी चलाने का पता चला है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुआवजा दिया गया है।

अपीलकर्ता की ओर से दो प्रस्तुतियाँ की गई हैं अर्थात -

(क) अधिनियम की खंड 163-ए के तहत पहले की याचिका को खारिज करने के बाद अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका विचारणीय नहीं थी।

(ख) लापरवाही से गाड़ी चलाना गलत था।

डी. डी. आर. एक्स का दृश्य। पी-53।

(3) इस पहले प्रस्ताव के समर्थन में कि वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं थी क्योंकि अधिनियम की खंड 163-ए के तहत पहले की याचिका खारिज कर दी गई थी, दीपाल पर भरोसा किया गया है।

गिरीशभाई सोनी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा 1 और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम धनबाई

कांजी गढ़वी और अन्य 2.विशिष्ट तर्क यह है कि अधिनियम की खंड 163-ए और खंड 166 के तहत उपचार अलग और अलग हैं और एक व्यक्ति उनमें से किसी एक को चुन सकता है।एक बार जब वह अधिनियम की खंड 163-ए के तहत उपचार का चयन कर लेता है, तो वह दूसरे उपचार के लिए फिर से प्रयास नहीं कर सकता है।

(4) जवाब में, दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की खंड 163-ए और 166 के तहत उपचार स्वतंत्र हैं और दावेदार दोनों का लाभ नहीं ले सकता है, हालांकि, चूंकि अधिनियम की खंड 163-ए के तहत याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया था, इसलिए अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका थी

बनाए रखने योग्य।दीपाल गिरीशभाई सोनी (ऊपर) में निर्णय नहीं है

इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित हुए।

(5) दीपाल गिरीशभाई सोनी (ऊपर) में एक संदर्भ दिया गया था

खण्ड पीठ के रूप में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दो न्यायाधीशों की पीठ पर संदेह किया

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हंसराजभाई बनाम

कोडाला और अन्य 3 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की खंड 163 के तहत कार्यवाही अंतिम थी और अधिनियम की खंड 165 के तहत कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। खंड 163-ए के विधायी इतिहास को देखने के बाद और वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद दीपाल गिरीशभाई सोनी (ऊपर) की बड़ी पीठ ने कहा कि दावेदार खंड 163-ए के साथ-साथ अधिनियम की खंड 166 के तहत किसी अन्य याचिका को पसंद नहीं कर सकता है। तैयार संदर्भ के द्वारा निष्कर्ष नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

"57. इसलिए, हमारी राय है कि धारा 163-ए और 166 दोनों के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए उपाय अंतिम और एक दूसरे से स्वतंत्र होने के कारण, जैसा कि वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है, एक दावेदार इसके तहत अपने उपायों को एक साथ आगे नहीं बढ़ा सकता है।एक, इस प्रकार, एक के लिए जाने का विकल्प चुनना/चुनना चाहिए

1 ए. आई. आर 2004 एस. सी. 2107

2 (2011) 11 एस. सी. सी. 513

खंड 163-ए या अधिनियम की खंड 166 के तहत कार्यवाही, लेकिन दोनों के तहत नहीं।

58. कोडाला (ऊपर) में दावेदार का यह तर्क कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार बिना किसी दोष के दायित्व के अतिरिक्त है, उचित रूप से खारिज कर दिया गया था। कोडाला (उपर्युक्त) के साथ सहमति में हमारी यह भी राय है कि अधिनियम की खंड 140 और 141 के विपरीत संसद अधिनियम की खंड 163-ए के संदर्भ में अतिरिक्त मुआवजा प्रदान नहीं करना चाहती थी।

59. इस प्रश्न पर विभिन्न कोणों से विचार किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, यदि अधिनियम की खंड 166 के तहत कार्यवाही में, खंड 163-ए के तहत मुआवजा प्राप्त करने के बाद, पुरस्कार विजेता यह साबित करने में विफल रहता है कि दुर्घटना चालक की ओर से लापरवाही के कारण हुई थी या यदि यह तथ्य पाया जाता है कि मृतक या पीड़ित स्वयं इसके लिए जिम्मेदार थे, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण कोई मुआवजा देने से इनकार करता है; क्या यह उसके अधिकार क्षेत्र में होगा कि वह संरचित सूत्र के आधार पर पहले से ही भुगतान की गई मुआवजे की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस करने का निर्देश दे?

इसके अलावा, यदि किसी मामले में न्यायाधिकरण प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिनियम की खंड 166 के तहत मुआवजा देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, तो क्या वह इसकी खंड 163-ए के संदर्भ में मुआवजा देने के लिए स्वतंत्र होगा।

60. उपरोक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, समायोजन या धनवापसी का सवाल हमेशा उस स्थिति में उठेगा जब यह माना जाता है कि अधिनियम की खंड 163-ए के तहत कार्यवाही में भुगतान की गई मुआवजे की राशि अंतरिम प्रकृति की है।"

(6) निष्कर्ष यह है कि अधिनियम की खंड 163-ए और 166 के तहत कार्यवाही स्वतंत्र प्रकृति की है और इसे एक साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और अधिनियम की खंड 163-ए के तहत कार्यवाही अंतरिम प्रकृति की नहीं है।

(7) धनबाई कांजी गढ़वी (उपरोक्त) में एक कांजी भाई के कानूनी उत्तराधिकारियों ने अधिनियम की खंड 166 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें मुआवजे का दावा किया गया था। 7,50,000-और उसके बाद अधिनियम की खंड 163-ए के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें मुआवजे का दावा किया गया था। 3,93,500-न्यू इंडिया एस्यूरेंस कं. लिमिटेड पर।

बिना किसी दोष के दायित्व का आधार।न्यायाधिकरण ने अधिनियम की खंड 163-ए के तहत याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के साथ रु. 2,65,500 का मुआवजा देने का आदेश दिया।इसके द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि हंसराजभाई बनाम कोडाला (ऊपर) को देखते हुए अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका को खारिज कर दिया जाए।न्यायाधिकरण ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।इसके बाद, अधिनियम की खंड 163-ए के तहत पुरस्कार के खिलाफ एक अपील दायर की गई जिसे सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया।इसके बाद दावेदार ने कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए खंड 166 के तहत याचिका दायर की और इसे जारी रखने की अनुमति दी गई।उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त मामला दायर किया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 166 के तहत एक याचिका को अधिनियम की खंड 163-ए के तहत एक याचिका में परिवर्तित किया जा सकता है।

दीपाल गिरीशभाई सोनी (ऊपर) पर निर्भरता, यह माना गया था कि

दावेदार अधिनियम की खंड 163-ए और 166 के तहत प्रदान किए गए दोनों उपायों को आगे नहीं बढ़ा सकता है।

(8) इस प्रकार, कानून यह है कि अधिनियम की खंड 163-ए और खंड 166 के तहत एक साथ कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें उपचार अलग और स्वतंत्र हैं। खंड 163-ए के तहत प्रदान किया गया उपाय नो-फॉल्ट लायबिलिटी के आधार पर है

और इसे एक दावेदार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जोड़ा गया है, जिसकी आय 5 लाख रुपये से कम है। 40, 000/- प्रति माह। उक्त कार्यवाहियां अधिनियम की खंड 140 के तहत होने वाली कार्यवाहियों के विपरीत प्रकृति में अंतिम हैं।

(9) तत्काल मामले में, हालांकि अधिनियम की खंड 163-ए के तहत दावेदार की याचिका को न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी, अपील में, अवार्ड को दरकिनार कर दिया गया था और एक निष्कर्ष वापस कर दिया गया था कि उक्त याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि दावेदार की आय रु। 40, 000/- प्रति माह। इन परिस्थितियों में, दावेदार पर गलती दायित्व के आधार पर अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका दायर करने पर कोई रोक नहीं थी।यह दो अलग-अलग और स्वतंत्र प्रावधानों का लाभ उठाने के बराबर नहीं है।यदि दावेदार ने अधिनियम की खंड 163-ए के तहत याचिका पर पारित पुरस्कार का लाभ उठाया था और तब अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका दायर की थी, तो अपीलकर्ता का यह तर्क देना सही होगा कि अधिनियम की खंड 166 के तहत याचिका पर रोक थी।कि मामला नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क को खारिज कर दिया जाना चाहिए।दूसरा विवाद एक्स पर आधारित है। पी-53, डी. डी. आर. हालाँकि मैंने वही पढ़ा है, लेकिन मैं इसे इस निर्णय में पुनः प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं क्योंकि यह देवनागरी लिपि में है।उक्त डी. डी. आर. में केवल इतना कहा गया है कि दुर्घटना अचानक और संयोग से हुई और दावेदार 708 पर कॉल नहीं करना चाहता था।

किसी भी आपराधिक कार्यवाही को शुरू करें।उसने यह नहीं कहा कि कोई जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना नहीं था।उपयोग किए गए शब्द 'अचानक' और 'इतफाक' हैं, जिनका अर्थ क्रमशः 'अचानक' और 'संयोग से' होता है।दावा याचिका में सकारात्मक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए उनके शपथ पत्र में, विशेष रूप से लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप लगाए गए हैं और जिरह में, केवल इतना कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुए समझाया गया था कि वह एक महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं करना चाहती थी।इस प्रकार, विद्वत न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि लापरवाही से गाड़ी चलाना और लापरवाही साबित हुई।

(10) उपरोक्त कारणों को देखते हुए, अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उघेश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

हस्ताक्षर:- 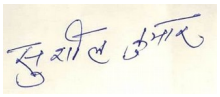

अनुवादक:- सुशील कुमार